other mechanism. I will co-operate with you fully.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think the Minister Sahib has given the entire policy for the future also. So, we can go to Question No. 104. *(Interruptions)*... आई नो। इस पर किसी और समय पर डिसकस करेंगे। दो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन आवर खत्म हो रहा है। जिचकर जी आपने तो क्वेश्चन पूछ लिया?

Apprehension regarding rise in the prices of Urea

*104. SHRIMATI BASANTI SARMA:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is an apprehension amongst farmers that the prices of urea will be raised;

(b) if so, Government's proposal to eliminate this apprehension from the minds of farmers; and

(c) the steps being taken to keep the prices of urea down?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) and (b) The price of urea has been increased by 10% with effect from 21.2.1997 for the present in order to reduce the imbalance in the application of NPK nutrients.

(c) The price of urea is already much lower compared to the decontrolled fertilizers. However, since the country's requirement of Urea is met through both indigenous production and imports, which is much costlier, any reduction in price of Urea is possible only if imports are avoided.

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Madam, a high-power committee headed by the noted economist, Shri Hanumantha Rao, was appointed to go into the entire gamut of the retention price mechanism of urea. When this question of hiking the price of urea by 10% had gone before the Cabinet Committee on Economic Affairs, a decision was deferred. An official spokesman of the Ministry said that there would be no hike in the price of urea until the Hanumantha Rao Committee gave its report. This was said on the 17th of February, 1997. On 17th February, an official spokesman of the other Ministry, that is, Mr. Ola's Ministry, said that there would be no increase in the price of urea and that the Cabinet had deferred a decision. On 21st February, they made an announcement that there would be an increase of 10% in the price of urea. Now what has happened in these four or five days necessitating this drastic decision?

श्री चतुरानन मिश्र: मैडम, माननीय सदस्य को कैबिनेट की जितनी जानकारी है उतनी शायद हम को नहीं है और हमारी लाचारी है कि हम रख भी नहीं सकते हैं। इसलिए इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हनुमंतराव कमेटी जो बनी है उसका दूसरा काम है। इसको भी देखेगी लेकिन उसका दूसरा काम है। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था जब माननीय सदस्य-गण पूछ रहे थे कि प्राइवेट कंपनी को ज्यादा पैसा मिल रहा है और वह ज्यादा लाभ उठा रहे हैं। मैं इसको सुन रहा था। लेकिन हमको अधिकार नहीं था। अब अधिकार है और हम आपको कहना चाहते हैं। यह ठीक है कि जो कैपिटल रिलेटेड एक्सपेंडीचर होता है उसकी 100 परसेंट कैपेसिटी होनी चाहिए। इसमें एक कंपनी ऐसी है, नाम लेना शायद उचित नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर की है, उसने अपनी कैपेसिटी 143 परसेंट दिखाई है और उस पर वह प्राइस लेता चला जा रहा है।

उपसभापति: नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। वह पुरुष या महिला नहीं है।

A company's name can be mentioned. You should not mention the names of those people who cannot defend themselves here.

श्री चतुरानन मिश्र: पुरुष और महिला ये तो सिर्फ हिन्दी में लागू होते हैं। संस्कृत में तीन जैंडर होते हैं।

उपसभापति: तीसरे जैंडर का नाम लेना अलाउड है।

श्री चतुरानन मिश्र: मैं उस कंपनी का नाम कह देता हूं। नागार्जुन फर्टिलाइजर कंपनी। इसने दिखला दिया 143 परसेंट। अब इसमें क्या है, उसको उत्पादन के लिए अलग से दाम बढ़ाकर देते हैं। अब अगर 143 पर पहुंच जाए तो अबसर्डिटी हो जाती है। लेकिन इसमें तय क्या है वह मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं। फर्टिलाइजर प्लांट में एक इन बिल्ट कैपेसिटी रहती है। वह एक्सीडेंटल है। जैसे अगर भूकम्प आ जाए तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए 5 प्रतिशत है, टेम्परचर डाऊन हो जाए या अप हो जाए, ऐसा कर के करीब 18 प्रतिशत इनबिल्ट रहता है। उसका पैसा भी वह ले लेते थे। इसीलिए राव साहब की अध्यक्षता में वह कमेटी बनी है जो जांच करे **(व्यवधान)** अध्यक्ष या जो भी सोचिए वही है, वह जांच करेगी, उसका इससे संबंध नहीं था यह जो वस्तु है जिसके बारे में हमारे फर्टिलाइज़र मंत्री महोदय ने कहा असंतुलित व्यवहार करने से भी खेत ऊसर हो रहा है, जो सॉयल की हेल्थ है वह बैडली अफेक्टेड हो रही है। पंजाब से ही रिपोर्ट आई है और कुछ साइंटिस्ट्स ने हमारे पास रिपोर्ट भेजी है कि यह एडवर्सिली अफेक्ट कर रहा है तो हमने बिना फाइनेंशियल बर्डन किये हुए जितना रुपया यूरिया से लिया उतना रुपया हमने किसानों को दूसरी फर्टिलाइज़र में दे दिया है। चूंकि यह प्रसारित हो रहा है इसलिए हमें इसको दोहराने की जरुरत नहीं है। अब उसी के संबंध में पूछा गया क्या कदम उठाया जा सकता है जिससे यूरिया का दाम सस्ता हो। यह आपके प्रश्न का अंश है। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जो आयातित यूरिया है, उसका दाम ज्यादा है। उसका दाम पड़ता है हैंडलिंग चार्ज लगा कर 8508 रुपये और जो अपने देश के अन्दर उत्पादन होता है उसका दाम पड़ता है 5600 रुपये। तो यह 3000 रुपये का फर्क दोनों में पड़ता है। रिटेंशन प्राइस तो हम अलग से देते हैं। यदि हम देश में होने वाले उत्पादन को बढ़ा दें तो हम इसे और सस्ता कर सकते है। इसलिए हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं। हमारे फर्टिलाइजर के माननीय मंत्री जी इस बात के लिए बहुत उद्यत हैं कि जो फर्टिलाइज़र प्लांट देश में बंद हैं उनको चालू करवा दें। अगर हम उसमें सफल हो जाते हैं तो 20-25 लाख टन और भी यूरिया अपने देश में उत्पादित हो जाएगा और आटोमेटिकली सबिस्डी भी कम हो जाएगी और दाम भी किसानों को सस्ता दे सकेंगे। यह जो बाहर से मंगवाते हैं अनिवार्य कारणों से, इनके चलते हमें ज्यादा मूल्य चुकाना पड़ता है। यूरिया के मुत्तालिक यह मामला है। हम इसके प्रयास में हैं कि वह जल्दी से जल्दी चालू हो जाएं तो हम इसको कर सकेंगे। इसके इलावा और भी कारण हैं गैस का दाम है, उनको हम देख रहे हैं। एक बात और कहना चाहता हूं। यह सही नहीं है कि पब्लिक सेक्टर के कारखाने को घाटा लगता है। देश के कोआप्रेटिव सेक्टर में इसको और कृभको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, जो आपका प्राइवेट सेक्टर भी नहीं दे रहा है। उनके जरिये कोशिश कर रहे है कि विदेशों में जहां फास्फोरिक एसिड है, जहां रॉक फॉसफेट है, वहां ज्वाइंट सेक्टर में कारखाने खोल लें तो हम पर भार कम हो जाएगा। ईरान या दूसरे देश हैं, वह कह रहे हैं कि हमारे यहां आ कर आप कारखाने खोलिए। हम अपनी कम्पनियों को कहते हैं कि ज्वाइंट सेक्टर में खोलें। हमारा ख्याल है कि इसमें कुछ टाइम लगेगा। चार पांच वर्ष तो लग जाते हैं किसी भी चीज में। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, जब हम अपने किसानों का सस्ता फर्टिलाइज़र दे सकेंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Narendra Mohan.

DR. SHRIKANT RAM CHANDRA JICHKAR: I want to ask my second supplementary.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, you are not the original questioner.

श्री नरेन्द्र मोहन: धन्यवाद, उपसभापति महोदया। कृषि मंत्री जी ने बताया कि जो यूरिया अपने देश में उत्पादित होता है उसकी कीमत कम है और विदेशों में ज्यादा है। इसलिए शायद आयातित यूरिया महंगा होता है। लेकिन एक बात मेरी जानकारी में यह है कि भारत में जो भी इस प्रकार के कारखाने यूरिया के हैं उनमें आधुनिकतम तकनीक और ज्ञान का प्रयोग नहीं होता है और जिस तकनीक का उत्पादन में प्रयोग होता है वह बहुत पुरानी है। इसके चलते अनेक कारखाने बंद हो चुके हैं, सात कारखाने बंद हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी गोरखपुर गये थे। वहां पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि कारखाना चालू हो जाएगा। अब आप कहते हैं कि समय लगेगा, इसमें भी समय लगेगा। आखिर आप यह बताएं कि हमारे जो कारखाने हैं क्या उनमें आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है और जो कारखाने बंद हैं, वह कब तक चालू हो जाएंगे। यह मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल है ...**(व्यवधान)**

उपसभापति: एक ही सवाल पूछ लीजिए। समय नहीं है। यह जवाब दीजिए मंत्री जी।

श्री नरेन्द्र मोहन: दूसरी इससे जुड़ी हुई बात यह है..

उपसभापति: इस सवाल का जवाब आने दीजिए। जुड़ा हुआ सवाल बाद में। एक तो आ जाए। यह लम्बा जवाब है इस सवा

श्री चतुरानन मिश्र: जहां तक यह बात है कि आधुनिकतम है, आधुनिकतम शब्द तो सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन आधुनिक मशीनरी है। कोआपरेटिव सेक्टर में—इफको और कृभको में। जो बंद और सिक कारखानों की बात आप कर रहे हैं उनका आउटमोडेड हो गया था। उनको जरूर माडर्नाइज करना है। उसमें हिंदुस्तान फर्टिलाइजर है, एफ॰सी॰आई॰ है। ये दोनों हैं। उसकी तरफ प्रयास हो रहा है कि उनको चालू करें।

श्री नरेन्द्र मोहन: कब तक चालू हो जाएंगे?

श्री चतुरानन मिश्र: कब तक हो जाएगा? यह कोई डिलीवरी है कि हम बता दें। कारखाना बनेगा तब होगा ...(व्यवधान)

उपसभापति: श्री नरेश यादव...

श्री नरेन्द्र मोहन: दूसरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है..

उपसभापति: बैठिए ..(व्यवधान).. नाट टु यू। मिस्टर यादव..

श्री संजय निरुपम: पिछले दस सालों से वे कारखाने बंद हैं। पूछ रहे हैं कब तक शुरू किए जाएंगे तो उन्होंने डिलीवरी बता दी ...(व्यवधान)...

उपसभापति: एक सेकिंड आप बैठिए ...(व्यवधान) आपको नहीं बुलाया है। यादव जी।

श्री संजय निरुपम: हम जानना चाहते हैं ....(व्यवधान)

उपसभापति: आप बैठिए Please sit down. This is not the way.

श्री नरेश यादव: महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री और माननीय उर्वरक मंत्री जी से यूरिया एवं अन्य उर्वरकों के बारे में जानना चाहता हूं। माननीय उर्वरक मंत्री जी ने यह बताया कि सेल्स टैक्स जो है उसका निर्धारण राज्य सरकारें करती हैं। निश्चित तौर से उर्वरकों पर सेल्स टैक्स राज्य सरकारें निर्धारित करती हैं। ऐसा हो जाता है कि कभी-कभी पड़ोसी राज्यों में कहीं टैक्स कम हो जाता है और कहीं बगल के राज्यों में टैक्स ज्यादा हो जाता है और ठीक समय पर, बोआई के समय या सिंचाई के समय यूरिया या अन्य उर्वरकों डी॰ए॰पी॰ या पोटाश में देश में मारा-मारी या हाहाकार मच जाता है और किसान इससे प्रभावित हो जाते हैं। जब हम चीनी का रेट पूरे देश में एक कर सकते हैं, गेहूं का रेट पूरे देश में एक कर सकते हैं वितरण का तो फिर क्या इन उर्वरकों की दर भी एक की जा सकती है जिससे कि किसानों में मारामारी न हो? धन्यवाद।

श्री एन॰के॰पी॰ साल्वे: गेहूं का रेट एक नहीं है।

श्री चतुरानन मिश्र: आपने तो दोनों मंत्रियों से पूछा है—पहले किसको...

उपसभापति: दोनों बोल दीजिए It is a joint responsibility.

SHRI CHATURANAN MISHRA: He said that he was addressing it to both the *Mantris*. I did not want to encroach upon anybody's right.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: पंडित जी, बिहार का मामला है।

श्री चतुरानन मिश्र: यह बिहार का नहीं, यह सारे राष्ट्र का है। आप कहें यह तो शोभा नहीं देता है। दूसरे आदमी कहें। आप तो सारे भारत को नचाए हैं। इसीलिए आप मत कहें।

श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे: आप डिलीवरी करें।

श्री चतुरानन मिश्र: जो प्रश्न उन्होंने कहा है वह बहुत सही है, आलोचना सही है। लेकिन देश में लोग मांग करते हैं कि फ्री ट्रेड हो ...(व्यवधान) जरा सुनिए। कहते हैं फ्री ट्रेड हो, पहले से तय हो गया। जब फ्री ट्रेड कर दिया तो कहते हैं दाम बांधो। दोनों बातें कैसे होंगी। कहे यह पार्लियामेंट कहती है कि फ्री ट्रेड हो। जब आप एक बार कह दिए तब तो यह होगा कि लोग दाम बढ़ाना शुरू करेंगे। हम तो उनकी मदद करते हैं। हम सब्सिडी भी नहीं देते हैं।

श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे: बढ़ाने में?

श्री चतुरानन मिश्र: नहीं बढ़ाने में तो नहीं देते हैं, घटाने के लिए देते हैं। बढ़ाने वाला तो आपने फ्री ट्रेड कर दिया और यह बच्चा लेकर हम घूम रहे हैं। समझ लीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री एन॰के॰पी॰ साल्वे: सब नाजायज बच्चे आपके सुपुर्द हैं।

श्री चतुरानन मिश्र: यह इनका बेबी लेकर हम चल रहे हैं। अब ये ही लोग मांग करते हैं कि आप कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं। दोनों बातें कैसे होंगी सो बता दीजिए। तभी तो किसानों की मदद के लिए हम असिस्टेंस आपको दे रहे हैं?

श्री अजीत जोगी: बेबी आपको पसंद तो आ गया है ना?

श्री चतुरानन मिश्र: कम्पलशन है। उस बच्चे को हम अनाथ छोड़ कैसे दें।

श्री नरेन्द्र मोहन: एडाप्ट कर लीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र: हो सकता है एडाप्ट करना पड़े। पिता को तो बहुत काम करने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता था मैडम कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को दिया गया और वे अपना-अपना टैक्स निर्धारित करती हैं। हम इसमें कैसे रोकेंगे उनको?

सेल्स टैक्स अलग है, प्राइस वह तय करते हैं। बिहार वालों का घाटा हो गया क्योंकि उनकी सरकार ने बहुत देर से तय किया तो नहीं पहुंच सका। यह घाटा जरूर हुआ। इस बार हमने यह प्रयास किया है हम माननीय सदस्यों से कहना चाहते हैं यह यूरिया का सेल का पीरियड नहीं है। अब आगे आएगा। गेहूं की फसल भी अभी चली गई है। यूरिया देने की बात नहीं है। बहुत कम देना है। यह इसलिए हमने अभी दाम तय कर लिया। हरेक राज्य सरकार को और डी०एम० को गोडाउन के लिए लिख कर भिजवा रहे हैं और कंपनियों को कह रहे हैं कि आफ् सीज़न में जितना प्रोडक्शन होता है वह डिस्टैंट एरिया में पहले ही जमा करके रख दें और पीक आवर्ज़ में हमको जो कहने लगते हैं कि आप स्पेशल ट्रेन दीजिए, यह दीजिए, इससे झंझट होता है। इसलिए हमने लिखा है। बिहार के मुख्य मंत्री को लिखा है और दूसरों को भी लिखा है। लोग गोडाउन बना लें और अभी जो प्रोडक्शन होता है हम भेज देंगे। नज़दीक वाले राज्यों को बाद में देंगे तो आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। यही मैं कहूंगा।

श्री नरेश यादव: मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैंने कहा है पूरे देश में सेल टैक्स में समानीकरण होना चाहिए।

श्री चतुरानन मिश्र: आप बताएं।

उपसभापति: जवाब दे दिया।

श्री चतुरानन मिश्र: जब पार्लियामेंट में फ्री ट्रेड का तय कर लिया तो उसमें हम क्या करेंगे। आप लोगों ने सब कुछ तय किया है।

श्री राघवजी: महोदया, माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि आयात किया हुआ यूरिया बहुत मंहगा पड़ता है और इसीलिए दाम बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके साथ-साथ कुप्रबन्ध भी है जिसके कारण दाम बढ़ता है। जैसा भंडारी जी ने बताया कि समय पर माल बाहर से आयात होता नहीं है। जहाजों में खड़ा रहता है। पोर्ट में उतर जाता है।

उपसभापति: आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री राघवजी: मैडम, मेरा प्रश्न यह है कि इस कुप्रबन्ध को सुधारने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है ताकि किसानों को यूरिया जब आवश्यकता पड़े उस समय मिल जाए और आपकी भी कीमत लागत कम हो जाए, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

श्री चतुरानन मिश्र: मैंने तो अभी कहा कि हरेक डी०एम० से कह रहे हैं कि पहले ही गोडाउन बना कर दे दें, वहां पहुँचा देंगे। यह कुप्रबन्ध तो नहीं हुआ, यह तो सुप्रबन्ध हुआ। उस दिशा में जा रहे हैं। अब पोर्ट वाला मामला कुछ टेढ़ा है क्योंकि पोर्ट की कैपेसिटी तो लिमिटेड है। फिर भी हम चाह रहे हैं कि पहले आ करके कर सकें।

श्री नगेन्द्र नाथ ओझा: महोदया, देश में यूरिया की कीमत की बात हो रही है। फर्टीलाइज़र मिनिस्टर ने कहा कि एक ही मौसम में बुवाई के समय यूरिया की जरूरत होती है। कृषि मंत्री जी से हम यह जानना चाहेंगे कि बुवाई के समय ज्यादा जरूरत पड़ती है या सिंचाई के समय या बुवाई के बाद, क्योंकि फर्टिलाइज़र मिनिस्टर कि बात देश को मालूम होने से बड़े अचम्भा में किसान पड़ेंगे कि हमारे फर्टिलाइज़र मिनिस्टर कहते हैं की बुवाई के समय ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। यह बेकार में कीमत की बात करने से क्या फायदा जब यही हमारे मंत्रियों को मालूम नहीं है कि यूरिया की जरूरतें कब पड़ती है। इसलिए यह देश के लोगों को क्लीयर हो जाए कि इस बारे में हमारे मंत्रियों का क्या कहना है?

श्री चतुरानन मिश्र: पता नहीं, हमने यह नहीं जाना कि फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने क्या कहा। हम तो ऐसा नहीं सुने हैं। लेकिन ऐसा होता है कि गेहूं की बुवाई के टाईम में डी०ए०पी० की पहले जरूरत हो जाती है उसको करते हैं और फिर थोड़े दिन के बाद यूरिया देते हैं तथा फिर पानी से उसको पटाते हैं। यह तो प्रोसैस रहता है। लेकिन एक स्टेज में आ करके जब उसमें दाना लगने लगे तब फिर हमको जरूर हो जाएगी। इसलिए यह लीन सीज़न था जिसमें हमने यह इंतजाम कर दिया।

श्री राजनाथ सिंह सूर्य: माननीया उपसभापति जी, अभी मंत्री जी ने यह कहा है कि वह डिलिवरी का समय नहीं बता सकते, लेकिन जो हैड मैटरन है जिसके कि ये सब सहयोगी है उन्होंने जुलाई में यह कहा था कि गोरखपुर का खाद कारखाना तीन महीने में चालू हो जाएगा। तो उन्होंने डिलीवरी का समय भी बता दिया था तो भाई लोगों ने मिल करके उस समय डिलिवरी अब तक क्यों नहीं कराई, क्या इसके बारे में कुछ बतायेंगे?

श्री चतुरानन मिश्रः यह पेपर्स से पूछिए। पेपर्स से पूछिए, वहां आप क्या बोले हैं। क्या अखबार में हम देखेंगे? और तीन महीने कहे हुए होंगे तो बात-चीत की जाएगी। ...(व्यवधान) हो सकता है...(व्यवधान) यह तो आप समझ ही सकते हैं ...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोहनः पूरे 9 महीने हो गए हैं, मंत्री जी।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Qustion Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Inauguration of Breeder Seed Processing and Storage Complex in Karnal

*101. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether he had recently inaugurated in Karnal the Indian Agricultural Research Institute (IARI) breeder seed processing and storage complex for 'adding flavour to foodgrains with Japanese aid,' as reported in "The Hindustan Times" dated 4th February, 1997;

(b) if so, the details thereof, cost involved, grant-in-aid received from Japan, including supply of required instruments for testing hygienic conditions of Indian fruits, etc.; and

(c) whether such seed processing and storage complexes are likely to be set-up in Rajasthan and Orissa?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) The Seed Processing and Storage Complex at Indian Agricultural Research Institute's Regional Station, Karnal was inaugurated on 1.2.1997. This complex is primarily meant for improving the quality of nucleus/breeder seed of improved varieties of agri-horticultural crops using modern processing and storage techniques as well as buffer stocking of the same. The complex in not for 'adding flavour to foodgrains' as reported in the "Hindustan times" dated 4th February, 1997.

(b) The details of the project are given below:—

1. Cost involved:

(a) Japan Grant-in-Aid received=662 million Yen (Rs. 21.50 crores approx.)

(b) Indian Contribution=Rs. 15.50 lakhs (for renovation of building, laboratories and maintenance of equipments received under this project during 1996-97.

2. Equipments received:

The equipments received at Indian Agricultural Research Institute's Regional Station, Karnal and Division of Seed Science Technology, New Delhi under this project are primarily for seed processing, storage and research. Important equipments are given in Statement (*See* below).

For creating hygienic conditions in Indian fruits, the Government of Japan has assisted Agricultural Produce Export Development Agency (APEDA), under a separate project, in establishing a Vapour Heat Treatment (VHT) facility at the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi for research and pilot scale testing of the use of this facility for dis-infestation (creating hygienic conditions) of mangoes and other fruits against fruitflies to promote export of these fruits.

(c) No, Sir.

Statement

Equipments received under the Japanese Grant-In-Aid at Iari Regional Station, Karnal.

1. *Processing & storing on field crops*

(i) Pre-cleaner;

(ii) Screen Grader;

(iii) Length separator;

(iv) Gravity Separator;

(v) Seed Treater;